मूल्य 1 रु.
वर्षः 11 - अंक : 216, मुंबई, शुक्रवार, 15 अक्टूबर, 2021 ■ RNI.NO. MAHHIN/2010/34146 ■ संपादकः दिलशाद एस. खान

दैनिक
मुंबई हलचल
भारत सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त R
अब हर सच होगा उजागर

महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर से खुलेंगे कॉलेज

दोनों डोज ले चुके विद्यार्थी ही अटेंड कर सकेंगे क्लास

मुंबई। राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने 20 अक्टूबर से राज्य के सभी गैर कृषि विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज 50 फीसद क्षमता के साथ खोले जाने की घोषणा की है। हालांकि कक्षाओं में वे ही विद्यार्थी बैठ सकेंगे, जिन्हें कोविड-19 की दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। मुंबई में विद्यार्थियों को लोकल ट्रेन से यात्रा की अनुमति देने के लिए मुख्य सचिव को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उधर, पुणे में सामंत की घोषणा से पहले ही 12 अक्टूबर से कॉलेज खोल दिए गए। प्रतिबंधित क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों और संबंधित कॉलेजों को स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेने को कहा गया है। बुधवार को मंत्रालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मंत्री सामंत ने कहा कि जिन विद्यार्थियों को अभी टीके नहीं लगे हैं, उनके लिए विश्वविद्यालय संबंधित संस्थाओं के प्रमुखों और कॉलेज प्राचार्यों के साथ स्थानीय जिला प्रशासन विशेष मुहिम शुरू करेंगे। इस मुहिम में 18 साल से ज्यादा आयु के विद्यार्थियों के साथ टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ के टीकाकरण को वरीयता देने को कहा गया है। (शेष पृष्ठ 3 पर)

स्कूल के पास शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी मंजूरी

मुंबई। स्कूलों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वे छात्रों के अंदर उच्च नैतिक मूल्य को पनपने के लिए मदद करें और उन्हें वैसा माहौल प्रदान करें। स्कूल के पास शराब परोसने वाले एक रेस्टोरेंट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी आधार पर खारिज कर दिया। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी ने कहा कि याचिकाकर्ता अदालत में जिरह के दौरान अदालत के सामने यह साबित करने में असमर्थ रहे कि उनके स्कूल द्वारा दी जा रही शिक्षा में शराब परोसने वाला रेस्टोरेंट बाधा बन सकता है और बच्चों पर इसका गलत असर हो सकता है।

समाजसेवकों ने दायर की थी याचिका

आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्टल संचालित करने वाले तीन सोशल वर्कर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यह मामला तब शुरू हुआ जब होटल मूनलाइट के मालिक ने पडली बाराव गांव से अपने शराब के ठेके को जुन्नर के शहरी इलाके में दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की। हालांकि साल 2019 में याचिकाकर्ता, स्थानीय लोग, शिरूर के सांसद और विधायक के विरोध के बाद स्थानीय जिलाधिकारी ने इसे मंजूरी नहीं दी। जस्टिस कुलकर्णी ने कहा कि ऐसा लगता है कि अत्यधिक राजनैतिक दबाव में जिलाधिकारी ने यह निर्णय दिया है। शराब के ठेके को जिस दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए आवेदन दिया गया था, वहां पास में एक स्कूल भी था। इसी वजह से जिलाधिकारी ने इसे रिजेक्ट किया था। (शेष पृष्ठ 3 पर)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- वरवर राव को 28 अक्टूबर तक आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में कवि-कार्यकर्ता वरवर राव को 28 अक्टूबर तक तलोजा जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति नितिन जमादार और एस वी कोतवाल की पीठ ने बृहस्पतिवार को राव को आत्मसमर्पण के लिए दी गई अवधि 28 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी और कहा अदालत आगे की सुनवाई 26 अक्टूबर को करेगी।

जमानत अवधि पर 26 अक्टूबर को सुनवाई - पीठ ने यह भी कहा कि उन्हें दी गई जमानत की अवधि बढ़ाने पर 26 अक्टूबर को सुनवाई की जायेगी। राव (82) को उच्च न्यायालय ने इस साल 22 फरवरी को मेडिकल आधार पर छह महीने के लिए जमानत दी थी। उन्हें पांच सितंबर को आत्मसमर्पण करना था और न्यायिक हिरासत में लौटना था। हालांकि, राव ने अपने अधिवक्ता आर सत्यनारायण और वकील आनंद ग्रोवर के मार्फत पिछले महीने एक अर्जी देकर जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। (शेष पृष्ठ 3 पर)

ड्रग्स केस में NCB और नवाब मलिक आमने-सामने

महाराष्ट्र के मंत्री ने दामाद को जमानत मिलने के बाद कहा- इखढ के इशारे पर बदनाम किया गया

मुंबई। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि उनके दामाद समीर खान को बीजेपी के इशारे पर फर्जी ड्रग्स केस में फंसाया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को उनके पास से कोई प्रतिबंधित नशीला पदार्थ नहीं मिला था। 9 जनवरी को समीर की पहचान के साहिस्ता फर्नीचरवाला के पास से साढ़े सात ग्राम हर्बल तंबाकू जब्त किया गया था। फॉरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि भी हुई, जबकि NCB ने 200 किलो गांजा जब्त करने का दावा किया था। मलिक ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कहीं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी एजेंसी ठउइ तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं कर पाती है।

मलिक ने कहा-जान से मारने की मिल रही है धमकी

मलिक ने यह भी कहा कि हाल ही में NCB के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस करने के बाद से उनके ऑफिस में हर दिन उन्हें जान से मरने की धमकी मिल रही है। बता दें कि राज्य सरकार ने मलिक के इस आरोप के बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। अब उन्हें वाई कैटगरी की सुरक्षा दी गई है। (शेष पृष्ठ 3 पर)

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

हमारी बात

गति-शक्ति अनिवार्य

भारत में विकास को गति देना बहुत जरूरी है और इस दिशा में किसी भी प्रयास का खुले मन से स्वागत होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पीएम गतिशक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की है। इससे देश में बुनियादी ढांचे का विकास तेज होगा और इस प्लान के तहत सरकार 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें कोई शक नहीं कि बुनियादी ढांचे या योजनाओं में इतने बड़े निवेश से लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस विशेष प्लान को अगर आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है, तो कोई आश्चर्य नहीं। इस प्लान का लक्ष्य 1.5 ट्रिलियन डॉलर की राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत परियोजनाओं को अधिक शक्ति व गति देना है। उम्मीद करनी चाहिए कि विकास के लिए निर्धारित धन जल्दी उपयोग में आए और देश के विकास में जल्दी बढ़त दिखे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम अगले 25 वर्ष के लिए नींव रख रहे हैं। वैसे यह प्लान एकदम नया नहीं है, इसकी चर्चा अगस्त महीने में ही शुरू हो गई थी।

इस प्लान से सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि जो परियोजनाएं ज्यादा जरूरी हैं, जिनमें रोजगार पैदा होने की ज्यादा गुंजाइश है, उनमें पहले खर्च करना होगा। यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान 21वीं सदी की विकास योजनाओं को तभी गति-शक्ति दे सकेगा, जब सरकारी अधिकारी पूरे समर्पण भाव से इस पर ध्यान देंगे। यह बात अनेक बार सामने आ चुकी है कि बुनियादी ढांचा विकास से जुड़े अनेक अधिकारी ऐसे हैं, जिनका झुकाव ठेकेदारों की तरफ ज्यादा रहता है। इस वजह से परियोजनाओं को पूरा करने में जरूरत से ज्यादा वक्त लगता है। सरकारी ढांचे में यह जो कमी है, उसे क्या गति-शक्ति के जरिये दूर किया जा सकेगा? क्या गति-शक्ति से अधिकारियों की नीयत में भी सुधार आएगा? अनेक बार यह बात होती है कि योजनाओं और संसाधनों की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके क्रियान्वयन में लगे लोगों की मंशा संदेहों के घेरे में रही है। गति-शक्ति के तहत यह भी देखना चाहिए कि काम न केवल समय पर हों, बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी हों। हमने अनेक पुलों को बनते ही टूटते-ढहते देखा है, लेकिन दोषी अधिकारियों का क्या हुआ, कितने लोग जानते हैं? आला अधिकारी अपने देश की इस कमी से वाकिफ हैं, उन्हें सचेत रहना होगा। गति-शक्ति प्लान नाम से ही जिस जल्दी की व्यंजना होती है, उसका प्रसार क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों तक होना चाहिए। इस प्लान को देश के बुनियादी ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा था कि गति-शक्ति प्लान विभागीय रुकावटों को खत्म कर देगा और समग्र योजना को संस्थागत रूप देगा। इस प्लान के तहत 16 मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियोजित और शुरू की गई ढांचागत विकास पहलों को एकजुट करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल की परिकल्पना की गई है, जिसका लाभ निचले स्तर तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचना चाहिए। लोगों को जमीनी स्तर पर इस प्लान का असर तब महसूस होगा, जब सड़कों पर अक्सर होने वाली खुदाई रुक जाएगी, जब सरकारी विभागों के बीच विकास कार्यों में समन्वय दिखने लगेगा। जब अधिकारी किसी काम के लिए किसी अन्य विभाग को दोषी नहीं ठहराएंगे और पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे और पूछने पर दावे के साथ सही जवाब भी देंगे।

टीके से नौनिहालों का बचाव

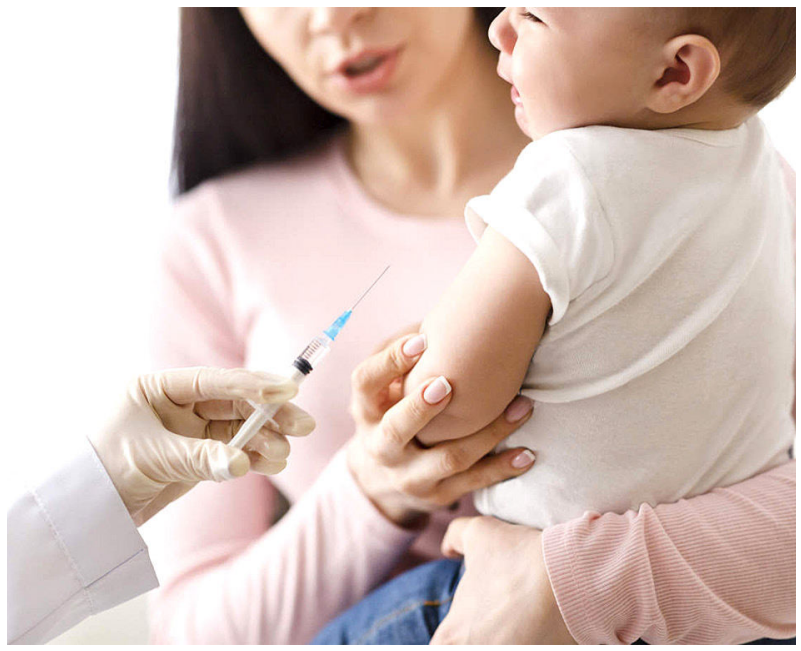

कोविड-19 से बचाव में टीकों की अहम भूमिका है, लेकिन अब तक उपलब्ध अधिकतर टीकों को वयस्क आयु-वर्ग के लिए ही आपात इस्तेमाल की अनुमति मिली है। वैसे, कुछ देशों में 12 से 17 साल के आयु-वर्ग में उच्च जोखिम वाले किशोरों का टीकाकरण शुरू हो गया है। और, इसी कड़ी में मंगलवार को भारत में सीडीएससीओ की विषय विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक की ह्यकोवैक्सीनह्ल को भी दो से 17 साल तक के बच्चों व किशोरों में इस्तेमाल करने के लिए मंजूर करने की सिफारिश की है। हालांकि, इन पंक्तियों के लिखे जाने तक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) की मंजूरी नहीं मिली थी। मगर इससे पहले, अगस्त में जाइडस कैडिला द्वारा विकसित जायकोव-डी वैक्सीन को 12 से 17 आयु-वर्ग के लिए डीसीजीआई आपात इस्तेमाल के लिए मंजूर कर चुका है। साथ ही, दो अन्य टीकों- 'कोवोवैक्स' और 'कोबीवैक्स' के भी बच्चों में परीक्षण हो रहे हैं।

इन खबरों से कई अभिभावक उत्साहित हैं कि अब बच्चों को भी टीके लगना शुरू हो जाएगा। मगर क्या वाकई बच्चों को कोविड-19 टीके की जरूरत है, इस पर सभी पहलुओं से और वैज्ञानिक आधार पर विचार करना होगा। पहली बात, किसी टीके को देश में 'परीक्षण और मंजूरी' और फिर उसके बाद किसी भी आयु-वर्ग के लिए 'इस्तेमाल की सिफारिश और शुरूआत' दो अलग प्रक्रियाएं हैं। कौन-सी वैक्सीन किस आयु-वर्ग के लिए जांची-परखी जाए, यह निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि उस बीमारी से किस आयु-वर्ग के लोग प्रभावित होते हैं। निस्संदेह, कोरोना ने सभी आयु-वर्ग को समान रूप से प्रभावित किया है, इसलिए कोविड- 19 के टीकों का बच्चों में भी परीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर ट्रायल में टीके, तय मानदंडों पर सुरक्षित और प्रभावशाली पाए जाते हैं, तो उन्हें उस देश में मंजूरी दे दी जाती है। मगर किसी वैक्सीन को देश में अनुमति मिलने का मतलब यह नहीं है कि उस आयु-वर्ग को टीके लगने शुरू ही हो जाएं। साल 2011 में जारी भारत की राष्ट्रीय टीकाकरण नीति में यह बताया गया है कि किसी भी टीके की अनुशंसा से पहले किस तरह के मानदंड का पालन किया जाना चाहिए। जैसे, किस आयु-वर्ग को बीमारी हो रही है, टीका कितनी सुरक्षा देगा और टीके लगाने के फायदे और खतरों पर विचार आदि। यह नीति टीकाकरण में किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इस बिंदु पर भी सुझाव देती है। वैक्सीन को मंजूरी मिलना यह आश्वस्त करता है कि जरूरत पड़ने पर उस आयु-वर्ग को टीके लगाए जा सकते हैं। लगाएं जाएं या नहीं और किस आयु-वर्ग को लगाए जाएं, इसकी सिफारिश अपने यहां राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह (एनटागी) देश की राष्ट्रीय टीकाकरण नीति के मानदंडों के आधार पर करती है। फिलहाल एनटागी ने बच्चों के लिए किसी कोरोना टीके की सिफारिश नहीं की है। पिछले 18 महीने में उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य यही बताते हैं कि संक्रमित होने के बावजूद बच्चों में गंभीर बीमार होने और मृत्यु की आशंका तुलनात्मक रूप से कम होती है। आईसीएमआर के सीरो सर्वे के मुताबिक, करीब 60 फीसदी बच्चे प्राकृतिक रूप से कोरोना-संक्रमित हो चुके हैं, जबकि उनमें अस्पतालों में भर्ती की दर कम और मृत्यु-दर बहुत ही कम है। एक सच यह भी है कि अभी भारत में उपलब्ध सभी कोरोना-रोधी टीके संक्रमण से नहीं बचाते, बल्कि इसकी गंभीरता को कम करते हैं। चूंकि वयस्कों में गंभीर बीमारी और मृत्यु की आशंका अधिक होती है, इसलिए उनको टीके की जरूरत कहीं ज्यादा है।

मंजूरी से पहले जहां यह विचार किया जाता है कि टीके कितने सुरक्षित हैं, वहीं हम यह भी जानते हैं कि बच्चों में टीकों के कुछ दुर्लभ दुष्प्रभाव वयस्कों से अधिक होते हैं। बच्चों में कोविड-19 टीकाकरण के लाभ तुलनात्मक रूप से कम और दुष्प्रभाव की आशंकाएं कुछ अधिक हैं। साथ ही, उपलब्ध आंकड़ा चूंकि 500 से 1,500 बच्चों पर टीके के परीक्षण का है और बच्चों में कोरोना वैक्सीन पहली बार लगाई जाएगी, इसलिए हमें किसी भी जल्दबाजी से बचना होगा। जोखिम वाले बच्चों के टीकाकरण से जो आंकडे.निकलकर सामने आएंगे, उसी के आधार पर देश के स्वस्थ बच्चों के टीकाकरण पर फैसला लेना उचित होगा। यही वजह है कि कोई भी देश बच्चों के टीकाकरण में जल्दबाजी में नहीं है। उंगलियों पर गिनने लायक जिन देशों में 12-17 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ है, अधिकतर में टीका उन्हीं बच्चों को दिया जा रहा है, जिनमें जोखिम सामान्य बच्चों से ज्यादा है। उम्मीद है, भारत में भी राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह लोक-लुभावन नीति के तहत या राजनीतिक दबाव में बच्चों के टीकाकरण पर निर्णय न देकर वैज्ञानिक आधार पर न्यायोचित फैसला लेगा।

अब जब बच्चों के टीके के लाइसेंस की चर्चा पुरजोर है, तब तमाम माता-पिता यह भी सोच रहे होंगे कि उनके बच्चों को टीका लगाने का वक्त आ गया है और जब उन्हें टीके लग जाएंगे, तभी उनको स्कूल भेजेंगे। मगर तमाम अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ एकमत हैं कि स्कूल खोलने के लिए बच्चों के टीकाकरण की कतई जरूरत नहीं है। बच्चों को स्कूल भेजने को टीकाकरण से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अभिभावकों में कोविड-19 टीकाकरण के बारे में और भी कई भ्रांतियां हैं। कोरोना-रोधी टीके को लेकर लोगों के आग्रही रवैये से पार पाने के लिए उनकी उलझनों को दूर करना भी जरूरी है। बच्चों में टीकाकरण के फायदे-नुकसान की बात आम लोगों को बोलचाल की भाषा में बताई जानी चाहिए। सरकार को उपलब्ध डाटा का इस्तेमाल करते हुए और पारदर्शी रूप से लोगों को बताना चाहिए कि बच्चों को कितना खतरा है और टीकाकरण के लिए आयु-वर्ग का चयन कैसे किया जाएगा? वयस्कों को कोरोना के गंभीर संक्रमण का खतरा अधिक है और उनके लिए टीकाकरण के आपात इस्तेमाल की मंजूरी तार्किक है, लेकिन जब बच्चों के टीकाकरण की बात आती है, तो विशेषज्ञों को आंकड़ों के आधार पर और संयम के साथ निर्णय लेने होंगे।

मालिक,मुद्रक,प्रकाशक-**दिलशाद एस. खान** द्वारा एस आर प्रिंटिंग प्रेस,मोहन अर्जुन कंपाउंड, वैशाली नगर दहिसर (पूर्व),मुंबई-68 से मुद्रित व मुंबई हलचल,साईं मंगल को ऑ हॉ सो बी-2-301,इस्माइल बाग नियर मालाड शॉपिंग सेंटर,एस वी रोड,मालाड (प) मुंबई से प्रकाशित RNI NO MAHHIN/2010/34146, **फोन:9619102478 /9821238815** email: mumbaihalchal@gmail com संपादक: **दिलशाद एस. खान**,
समाचार पत्र में छपे किसी भी समाचार से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा न्याय क्षेत्र मुंबई होगा।

दैनिक
मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

मुंब्रा बाजार में मनपा प्रशासन की अतिक्रमण विभाग की तोड़ू कार्रवाई

संवाददाता/समद खान

मुंब्रा। गत 13 अक्टूबर बुधवार को रेलवे स्टेशन से सटा परिसर मुंब्रा बाजार में मनपा प्रशासन के अतिक्रमण विभाग द्वारा तोड़क कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई हॉकर्स द्वारा छपरा रास्ते पर लगाए जाने को लेकर की गई। और रास्ते पर व्यवसाय कर रहे लोग जैसे कि कपड़ा बेचने वाले ठेला लगाने वाले हैं। फल फ्रूट विक्रेता अचार पापड़ विक्रेता ऐसे अनेक ठेले वाले। इन लोगों की वजह से रास्ते पर लोगों का चलना मुहाल हो जाता है। जनता की दिक्कतों को देखते हुए मनपा प्रशासन के अतिक्रमण विभाग द्वारा तोड़क कार्रवाई की गई। हालांकि यह कार्रवाई इतनी बड़ी नहीं थी क्योंकि हॉकिंस को मानपा प्रशासन ने 2 घंटे का समय दिया। वह अपने छपरा निकाल ले ताकि लोगों का ज्यादा नुकसान ना हो उस पर भी होकर द्वारा यह छपरे नहीं निकाले गए। फिर मानपा प्रशासन के अतिक्रमण विभाग ने अपनी तोडक कार्रवाई को अंजाम दिया। हॉकर्स वालों को और दुकानदारों को चेताया है। अगर दोबारा चपरे रास्ते पर नजर आए तो फिर मानपा प्रशासन का अतिक्रमण विभाग का दसता फिर कार्रवाई करेगा।

दो शातिर ठगों को शील डायगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

टोरेंट बिल कम कराने का झांसा देकर लोगों को बनाते थे अपनी ठगी का शिकार

संवाददाता/समद खान

मुंब्रा। शातिर ठग शील डायगर पुलिस के उस वक्त हत्थे चढ़ा जब दिवा के रहवासी कैलाश चंद कुमावत ने उनके साथ हुई ठगी की शिकायत पुलिस मे की मामले का खुलासा करते हुए शिकायतकर्ता ने बताया कि मेरा टोरेंट का बकाया बिल 68340 रुपए था। मुझे किसी व्यक्ति द्वारा फोन किया गया। और कहां गया कि तुम्हारा बिल का भुगतान दो दिन में करो अन्यथा तुम्हारी बिजली काट दी जाएगी। फिर मैंने जिस व्यक्ति ने मुझे फोन किया था। उसको संपर्क किया तभी उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि तुम्हारा बिल में सेटलमेंट कर कम करा देता हूं। तुम मुझे ₹34 हजार दे दो मैं तुम्हारा बेल कम करवा दूंगा। मैंने उस व्यक्ति पर भरोसा करके पैसे दे दिए। और जब मुझे दोबारा बिल आया मुझे वही रकम देखने को मिली मैंने इसकी शिकायत पुलिस में की पुलिस ने तत्परत दिखाते हुए इन ठगों को अपने गिरफ्त में ले लिया। यह ठगों का नाम रफीक शेख और अब्दुल्लाह शेख मुंब्रा के रहवासी बताए जा रहे हैं। कथित तौर पर पूछताछ के बाद पता चला कि यह दोनों ठगों ने अपनी ठगी का शिकार 28 लोगों को बनाया है। और उनसे वसूली की गई रकम 19 लाख रुपए बताई जा रही है। ठाणे पुलिस आयुक्तालय के डीसीपी अविनाश अंबुरे ने पत्रकार परिषद कर इन ठगों के बारे में जानकारी देते हुए बताया यह दोनों ठगों ने मुंब्रा दिवा के टोरेंट के ग्राहकों का बकाया बिल सेटलमेंट करा कर कम करने का झांसा देकर उपभोक्ताओं से मोटी रकम वसूल किया करते थे। शील डायगर पुलिस की बड़ी कामयाबी का सेहरा एपीआई बृजेश शिंदे और उनकी टीम को पहनाया गया। और साथ-साथ तीन घर पूड़ी के और दो बाइक चोरों का केस क्रैक किया गया। और मुंब्रा दिवा की जनता से आह्वान किया है कि, अगर इन ठगों की ठगी का शिकार कोई भी उपभोक्ता बना है। तो तुरंत पुलिस से शिकायत करें और ऐसे शातिर ठगों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। शील डायगर पुलिस ने इस धोखाधड़ी जालसाजी चेक हेरफेर के मामले में भारतीय दंड संहिता धारा 420 419 467 468 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ा कांग्रेस पार्षद

मुंबई। भिवंडी महानगरपालिका के एक कांग्रेस पार्षद को 50 लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए ठाणे एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत यह पार्षद विस्थापित दुकानदारों को उनकी दुकान दिलाने के नाम पर ले रहा था।

कांग्रेस पार्षद सिद्धेश्वर कामूर्ती को देर शाम ठाणे एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने 50 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल इस मामले के शिकायतकर्ता राजकुमार चव्हाण ने दावा किया है कि भिवंडी के पद्मानगर में उनकी और कुछ अन्य लोगों की दूकान थी। जहां इस मार्ग का विस्तारीकरण होने के दौरान उनकी दुकानों का कुछ हिस्सा महानगर पालिका ने तोडा और उस दौरान मौखिक तौर पर दुकानों के बचे हिस्से को बनाने की अनुमति इन दुकानदारों को दी थी। हालांकि यह निर्माणकार्य अवैध है तो इन लोगों को फिर से दूकान बनाने देने के नाम पर कांग्रेस पार्षद सिद्धेश्वर कामुर्ती 2 करोड़ रुपयों की रिश्वत मांग रहा था और आज 50 लाख की रिश्वत लेते हुए कांग्रेस पार्षद सिद्धेश्वर कामुर्ती को ठाणे एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

(पृष्ठ 1 का शेष भाग)

महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर से खुलेंगे कॉलेज...

गाइडलाइंस नहीं मानी, तो होगी कार्रवाई - मंत्री सामंत ने कहा कि सभी कॉलेज-यूनिवर्सिटीज को केंद्र और राज्य सरकार की समय-समय पर जारी गाइडलाइंस, एसओपी का पालन करना जरूरी होगा। जो विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से कॉलेजों में उपस्थित नहीं हो सकेंगे, उन्हें ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सामंत ने कहा कि अलग-अलग चरणों में छात्रावास शुरू करने को लेकर संचालक उच्च शिक्षा और तकनीकी समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करें।

विद्यार्थियों को लोकल का इंतजार - मंत्री सामंत ने कॉलेज शुरू करने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन लोकल ट्रेन से आने-जाने की अनुमति नहीं दी है। इस बारे में सामंत ने कहा कि लोकल ट्रेन से आने वाले विद्यार्थियों को यात्रा की अनुमति मिलना आवश्यक है, इसके लिए मुख्य सचिव को प्रस्ताव भेजा गया है।

सरकारी अनुमति को लेकर भ्रम की स्थिति - पुणे में मंत्री उदय सामंत की घोषणा से पहले ही कॉलेज खोल दिए गए हैं, लेकिन सरकारी अनुमति को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दरअसल, पुणे नगर निगम ने एक आदेश जारी किया था कि जिसने टीके की दोनों खुराक ले ली हैं, वे प्रत्यक्ष कक्षाएं शुरू कर सकते हैं, लेकिन सरकार का कोई आदेश न मिलने से प्रबंधन भ्रम में है। आज भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र राज्य प्रधानाचार्य संघ के महासचिव सुधाकर जाधवर ने बताया कि हम राज्य के उच्च शिक्षा विभाग और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से स्पष्ट निदेर्शों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश कॉलेज इससे संबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक लेने वाले छात्रों की संख्या कम है। पीएमसी के दायरे में कम से कम 450 कॉलेज आते हैं। इस बीच स्वायत्त संस्थान फर्ग्यूसन कॉलेज में मंगलवार को प्रत्यक्ष कक्षाएं शुरू हो गईं। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. रवींद्र सिंह परदेशी ने कहा, हमने नियमों का पालन करते हुए सीनियर कॉलेज विंग को प्रत्यक्ष कक्षाओं के लिए फिर से खोल दिया है।

स्कूल के पास शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट...

स्कूल की वजह से नहीं मिली इजाजत - जांच अधिकारी की रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी ने कहा था कि मार्च 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल का मेन गेट रेस्टोरेंट से 450 मीटर की दूरी पर था। अगस्त 2019 में एक नया गेट पाया गया, जो कंपाउंड की दीवार के उत्तर पश्चिम में 144 मीटर दूर था। बॉम्बे फॉरेन लिकर रूल के मुताबिक किसी स्कूल या धार्मिक स्थल और शराब के ठेके या दुकान के बीच 75 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इस इलाके में एक अन्य होटल ऐसे ही लाइसेंस के साथ कई वर्षों से शुरू है जो 375 मीटर दूर है, जिस पर स्कूल ने विरोध नहीं किया।

ड्रग्स केस में NCB और नवाब मलिक आमने-सामने...

समीर को जमानत पर रिहा किया गया - नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इससे कुछ देर पहले ही मुंबई की एक विशेष अदालत ने समीर खान को जमानत दी थी। हालांकि, NCB ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार सेलिब्रिटी मैनेजर राहिल फर्नीचरवाला और ब्रिटिश नागरिक करन सेजनानी के साथ पकड़ा गया था। NCB ने इन पर ड्रग्स जमा करने, उसे बेचने और खरीदने का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक, NCB उनके खिलाफ अदालत में पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई। NCB ने समीर को ड्रग्स मामले में 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उनके पास से बड़ी मात्रा ने नशीला पदार्थ मिला था।

11 नमूनों की जांच में गांजा होने की पुष्टि नहीं - NCB की तरफ से आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद जुलाई में दायर जमानत याचिका में फॉरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि 18 में से 11 नमूनों की जांच में गांजा होने की पुष्टि नहीं हुई है। NCB ने दावा किया कि ज्यादातर ड्रग्स सेजनानी के पास से जब्त की गई, जो कि खान के साथ ड्रग्स के धंधे में शामिल थे। हालांकि, NCB खान और सेजनानी की मिलीभगत के सबूत नहीं पेश कर सकी। खान की गिरफ्तारी के बाद NCB ने 14 जनवरी को उनके बांद्रा स्थित घर समेत वसोर्वा, खार, लोखंडवाला, कुर्ला और पवई इलाकों में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था। हालांकि, उसे बाद में छोड़ दिया गया।

पहले अदालत ने खारिज की थी खान की याचिका - पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण NDPS अदालत ने सेलिब्रिटी मैनेजर राहिल फर्नीचरवाला और ब्रिटिश नागरिक करन सेजनानी को 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया। इससे पहले खान की जमानत याचिका दो बार मामले में जांच की बात कहते हुए अदालत की ओर से खारिज कर दी गई थी। हालांकि, मामले में NCB ने चार्जशीट भी दायर कर दी है। खान ने अदालत में तर्क दिया कि उन्हें एक सह-आरोपी के बयान के आधार पर झूठा फंसाया गया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- वरवर राव को...

हैदराबाद में ठहरने की अनुमति - राव ने जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान अपने गृह नगर हैदराबाद में ठहरने की अनुमति भी मांगी थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले की जांच कर रहा है। एनआईए ने मेडिकल जमानत बढ़ाने की राव की याचिका और हैदराबाद जाने देने के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट इस बारे में संकेत नहीं देती है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है।

द हुमन योगा फाऊंडेशन के तरफ से वर्ली में स्वच्छता अभियान किया

मुंबई। दिनांक 14 अक्टूबर द हुमन योगा फाऊंडेशन के तरफ से वर्ली स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम में, द हुमन योगा फाउंडेशन के सभी बच्चों ने मिलकर स्वच्छता अभियान के सभी नियमों का पालन किया। पूरा गार्डन साफ किया और उसके बाद सभी बच्चों ने स्वच्छता का अभियान जारी रखने के लिए सभी लोगों को राधेश्याम जी ने अस्वच्छ अच्छी तरीके से हरदम करने के लिए कही। और पूरा परिसर साफ करते करते सभी बच्चों को यह सीख मिल गया कि अपना अपना घर या परिसर हो हर जगह स्वास्थ्य स्वच्छता का ध्यान जारी रखना चाहिए, इसके अलावा ऑफिस आसपास की दिखाई देती हुई गंदगी को हमें हर दम साफ कर देना चाहिए, जिसके वजह से मच्छर नहीं लगेगा प्रदूषण नहीं होगा और हमारा परिसर साफ हरदम रहेगी। नेहरू युवा केंद्र एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार व द हुमन योगा फाउंडेशन के तत्वधान में इस कार्यक्रम का आयोजन योग गुरु राधेश्याम के माध्यम से हुआ। कार्यक्रम में फाउंडेशन के बच्चे और योग गुरु राधे श्याम ने कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तार रूप से समापन किया, जय हिंद जय भारत।

क्या है बीएसएफ का मुद्दा

2 राज्यों में अधिकार क्षेत्र से जुड़े नए नियम लागू, पर दो ही राज्यों में विरोध ज्यादा क्यों?

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय के नए एलान के मुताबिक अब बीएसएफ के अधिकारी पंजाब, बंगाल और असम जैसे राज्यों में सीमा के अंदर 50 किलोमीटर के दायरे में गिरफ्तारी, सर्च अभियान और जब्ती जैसी कार्रवाई का फैसला खुद ले सकेंगे। पहले बीएसएफ को ये ताकतें सीमा से सिर्फ 15 किमी तक के दायरे में दी गई थीं। जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला राजनीतिक मकसद से नहीं, बल्कि सीमाई इलाकों पर सुरक्षाबलों की क्षमताओं को मजबूत करने और तस्करी के नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने के लिए लिया गया है, वहीं

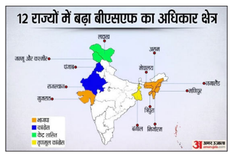

विपक्ष द्वारा शासित राज्यों की सरकार ने केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर ले लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने तो इस कदम को भारत के संघीय ढांचे पर हमला करार दे दिया।

सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान भेजता था लक्ष्मी नगर से पकड़ा गया आतंकी अशरफ

नई दिल्ली। लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अशरफ 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने हुए बम धमाकों में भी शामिल था। सेल से जुड़े सूत्रों का दावा है कि उसने धमाकों से पहले रेकी की थी। इतना ही नहीं, उसने दिल्ली पुलिस मुख्यालय और आईएसबीटी की रेकी भी की थी। कुछ दिनों तक वह कोलकाता और फिर अजमेर में रहा। इसकी ईमेल में ड्राफ्ट के जरिए आईएसआई से बातचीत होती थी।14 दिन की रिमांड पर लेने के बाद स्पेशल सेल के अलावा अशरफ से कई सुरक्षा एजेंसियों ने भी पूछताछ की है। उसके खुलासे पर उन लड़कों की तलाश में छापेमारी चल रही है, जो आतंकी हमले की साजिश का अहम हिस्सा थे। ये वॉट्सऐप चैटिंग से कॉल और चैट के जरिए स्लीपर मॉड्यूल से जुड़े लोगों से बात करता था, फिर उसे डिलीट कर देता था। पुलिस चैटिंग को खंगालने के लिए इसके दोनों मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रही है। सूत्रों ने बताया, 2009 में जम्मू बस स्टैंड पर बम ब्लास्ट में शामिल रहा है। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में धमाके के लिए 2 आतंकी आए थे, जिनमें से एक का नाम गुलाम सरवर था। सूत्रों का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में अक्सर हथियार सप्लाई करने जाता था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल जिले के कोटली सिधवान गांव के रहने वाले मोहम्मद अशरफ के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। इसके तीन बहनें और एक भाई है। इसका झुकाव जेहाद की तरफ हो गया था। आईएसआई ने ट्रेनिंग दी। 2004 ढाका भेज दिया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रास्ते वो भारत में दाखिल हुआ था। अशरफ 2005 में अजमेर में रहता था। वहां उसे झाड़-फूंक की आड़ में खुद को छिपाए रखा। फकीर की वेशभूषा में ही वो कई इलाकों की रेकी किया करता था। वहां अजमेर दरगाह के आसपास घूमता था। उसने देश के कई हिस्सों की रेकी की थी।

प्रभाग रचना को लेकर अमरावती में मुस्लिम समाज के राजनीतिक व सामाजिक संगठन प्रतिनिधि मंडल ने मनपा आयुक्त से मांग की

अमरावती महानगरपालिका में होने जा रहे आगामी म न पा चुनाव में प्रभाग रचना को लेकर अमरावती शहर पश्चिमी क्षेत्र विशेष तौर से (मुस्लिम समाज) के सभी राजनीतिक पार्टियों के व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मनपा आयुक्त साहब से मिलकर एक निवेदन सादर किया। निवेदन में यह मांग की गई जो प्रभाग रचना की जाती है। जिसमें ऐसे कुछ प्रभाग होते है। जिनकी रचना ऐसी की जाती है। ना ही कोई गाइडलाईंस चुनाव आयोग की ध्यान में रखते हुए नियम को ताक में रखकर बनाया जाता है। जिसकी वजह से ऐसे कई मुस्लिम बहुल क्षेत्र के कुछ क्षेत्र का भाग दूसरे प्रभाग में चले जाने से वहां मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं मिल पाता मुस्लिम जनप्रतिनिधियों की संख्या कम हो जाती है। जिसकी वजह से क्षेत्र का विकास व बहुत सी समस्याओं का वहां के क्षेत्र के लोगों को सामना करना पड़ता है। इस मुद्दे को लेकर प्रतिनिधि शिष्टमंडल म न पा पहुंचा जिसमें सैयद अफसर अली साहब, अब्दुल रहमान साहब, इमरान अशरफी, इरशाद पठान, सलमान खान एटीएस, मोहसिन अहमद, गटनेता अब्दुल नाजिम, सलाउद्दीन खान, जकीमुल्ला, अब्दुल राजिक, आसिफ भाई तवक्कल, अब्दुल नसीम पप्पू, हाजी रफीक, यासिर भारती, अब्दुल नईम, सादिक शाह, शफीक राजा, सनाउल्लाह खान सर, वहीद खान, सलीम खान, इमरान खान, गाजी जहेरोश सर, एड शोएब खान, हबिब ठेकेदार, सैयद साबीर, शेख इसरार आलम, डॉ असलम भारती, नासिर सोलंकी, यह्याया खान पठान, बब्बू भाई ड्राइवर।

दिनांक 13 अक्टूबर को सचिन मित्र मंडल द्वारा प्रेरित महिला उत्थान पर एक परिसंवाद का शिव सम्राट फाउंडेशन ने मालवणी 5 नम्बर पे आयोजन किया जिसमें एडवोकेट शेख सईद ने भारी संख्या में उपस्थित महिला ओ को कानूनी मार्गदर्शन दिया साथ में अब्दुल शैख, मंगेश चौधरी, पूजा लहाने, फातिमा कुरैशी, हसीना शेख और अन्य समाजसेवक मौजूद थे, आयोजक सम्राट बागुल जी ने सब का धन्यवाद किया !

केजरीवाल ने उपराज्यपाल को लिखा पत्र

दिल्ली में बेहतर है कोरोना की स्थिति, मिलनी चाहिए पूजा की अनुमति

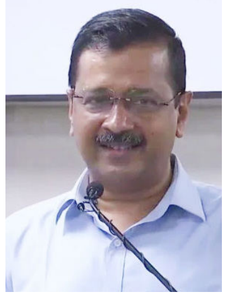

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में महापर्व छठ को लेकर असमंजस बरकरार है। दिल्ली सरकार ने इस बाबत गाइडलाइंस जारी करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र पहले ही लिख दिया है। इसी बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को भी इस संबंध में पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति अब बेहतर है। मेरे ख्याल से कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमें दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन की अनुमति दे देनी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी, सड़कों पर उतर आई

छठ पूजा को लेकर दिल्ली में राजनीति गरमा गई है। कोरोना को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों, जलाशयों और नदी किनारों पर छठ पूजा को लेकर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आई है।

अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया

दिल्ली भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने छठ पूजा पर रोक के विरोध में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी घायल हो गए थे और उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था।

27 सीटों पर पूर्वांचल मतदाताओं का प्रभाव

दिल्ली में छठ पूजा को लेकर राजनीति होना कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में करीब 40 लाख पूर्वांचली (यूपी-बिहार के) मतदाता हैं जो छठ पूजा करते है। उन्हें साधने के लिए कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी में होड़ लगी रहती है। दिल्ली की 27 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पूर्वांचल के लोग चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। इसी वजह से सियासी दल भी पूर्वांचल मतदाताओं पर जमकर दांव लगाते रहे हैं।

प्रदूषण पर सख्ती

तालाब या यमुना में नहीं कर सकेंगे दुर्गा मूर्ति विसर्जन, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने लगाई रोक

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) ने दुर्गा विसर्जन से पहले आदेश जारी कर यमुना, जल स्रोत, तालाब, घाट या सार्वजनिक स्थान पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन करने पर रोक लगा दी है। साथ ही लोगों से घरों में ही मूर्ति विसर्जन करने के लिए कहा है। डीपीसीसी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए मूर्ति कलाकारों से मूर्ति पर ऐसे किसी भी प्रकार का रंग या सामग्री इस्तेमाल करने से मना किया है, जिससे पानी को नुकसान पहुंचे और लोगों के स्वास्थ्य पर भी खराब असर पड़े। मूर्ति को प्राकृतिक मिट्टी से तैयार करने के लिए कहा गया है। साथ ही डीपीसीसी ने संबंधित एजेंसियों को प्रत्येक शुक्रवार को रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि दुर्गा पूजा पर नदी, झील, तालाब, कुएं आदि में मूर्ति विसर्जन की परंपरा है और इससे होने वाला प्रदूषण चिंता का विषय है। डीपीसीसी ने कहा है कि मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों को होने वाले नुकसान का आकलन किया गया है। डीपीसीसी ने मूर्ति बनाने के लिए पीओपी और पकी हुई मिट्टी के प्रयोग पर रोक लगा दी है। वहीं ये भी कहा है कि विसर्जन से पहले मूर्तियों से फूल और कागज निर्मित अन्य सजावटी वस्तुओं को हटाने और उन्हें घरों से इकट्ठा कर उनका पर्यावरण अनुरूप तरीके से निपटारा किया जाए।

अमरिंदर सिंह से अचानक मिलने पहुंचे सीएम चन्नी, हाईकमान से मिलेंगे सिद्धू

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गुरुवार को मोहाली के सिसवां स्थित कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस पर मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी की यह कैप्टन से पहली मुलाकात है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम और बेटे की शादी से भी दूरी बना रखी थी लेकिन अचानक इस मुलाकात ने पंजाब की सियासत को गर्मा दिया है।

मुलाकात की टाइमिंग बेहद अहम - कैप्टन अमरिंदर सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी की मुलाकात की टाइमिंग बेहद अहम है। एक ओर जहां नवजोत सिंह सिद्धू हाईकमान के सामने आज (गुरुवार) पेश होंगे तो वहीं उससे ठीक पहले चन्नी और कैप्टन की मुलाकात की खबरों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार हाईकमान से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान पार्टी में सिद्धू के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी हो सकता है।

कैप्टन कर चुके हैं चन्नी की तारीफ - मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निजी हमला बोला लेकिन वे चन्नी की कई मौकों पर तारीफ कर चुके हैं। कैप्टन ने चन्नी को बेहतरीन और पढ़ा-लिखा मंत्री बताया था। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा था कि चन्नी को गृह मामलों की समझ कम है।

चन्नी सरकार के फैसलों से खफा सिद्धू - चन्नी सरकार ने इकबालप्रीत सिंह सहोता को राज्य का डीजीपी का कार्यभार सौंपा। वरिष्ठ वकील एपीएस देओल को महाधिवक्ता बनाया। सिद्धू इन दोनों फैसलों से बेहद खफा थे। यही वजह है कि उन्होंने अचानक प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर हाईकमान को भी चौंका दिया था। अभी तक सिद्धू ने इस्तीफा वापस नहीं लिया है और न ही हाईकमान ने कोई फैसला किया है। इस बीच सिद्धू ने बिजली के मुद्दे पर चन्नी सरकार को घेरा।

इस मुद्दे पर कैप्टन व चन्नी कर सकते हैं चर्चा - केंद्र सरकार ने पंजाब समेत तीन राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में इजाफा किया है। इसके बाद से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। पंजाब सरकार ने जहां एक ओर इसे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल बताया तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फैसले की तारीफ

की। पंजाब में पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किमी के दायरे में बीएसएफ को कार्रवाई की अनुमति थी लेकिन अब यह दायरा 50 किमी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि चन्नी कैप्टन से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

मनीष हत्याकांड

पति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मीनाक्षी ने उठाया सवाल

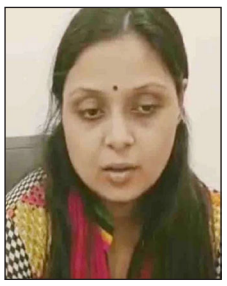

मीनाक्षी लगातार जांच पर सवाल उठा रही हैं... खासकर पुलिस की जांच को लेकर उनके भीतर शुरू से ही अविश्वास रहा है... इसलिए उन्होंने कानपुर पुलिस से जांच कराने की मांग की थी... हालांकि वह सीबीआई जांच ही चाहती हैं...

कानपुर। मनीष गुप्ता हत्याकांड के मामले में उनकी पत्नी मीनाक्षी ने ट्विटर पर पोस्ट कर जांच पर कई सवाल उठाए हैं। मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुबूतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर सीबीआई जांच कब होगी।

मीनाक्षी ने जिस तरह से एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए हैं वह बेहद गंभीर हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार पुलिस अफसर इसको किस तरह से लेते हैं। मीनाक्षी ने ट्विटर पर मनीष की फोटो शेयर करते हुए उसके कान का हिस्सा मार्क किया है।

साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पेज पोस्ट कर लिखा कि फोटो में चोट के निशान हैं। तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं हैं। जांच संदेहास्पद है। आखिर सीबीआई जांच कब होगी। मीनाक्षी का कहना है कि गोरखपुर पुलिस पर किसी तरह का भरोसा नहीं था। इसलिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी।

मगर दो सप्ताह से अधिक का समय बीत गया है लेकिन सीबीआई जांच के बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा है। आखिर सीबीआई जांच में देरी क्यों की जा रही है। उनका कहना है कि वर्तमान में जांच कम सुबूतों से खिलवाड़ अधिक किया जा रहा है।

शुरू से ही जांच पर सवाल उठा रही हैं मीनाक्षी

मीनाक्षी लगातार जांच पर सवाल उठा रही हैं। खासकर पुलिस की जांच को लेकर उनके भीतर शुरू से ही अविश्वास रहा है। इसलिए उन्होंने कानपुर पुलिस से जांच कराने की मांग की थी। हालांकि वह सीबीआई जांच ही चाहती हैं। मीनाक्षी का कहना है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं करेगी तब तक न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने एसआईटी की जांच पर संतुष्टि भी जाहिर की है। अब एक बार फिर पीएम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं।

कोविड अपडेट

यूपी में ढ़ाई करोड़ से ज्यादा लोगों ने ली कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज

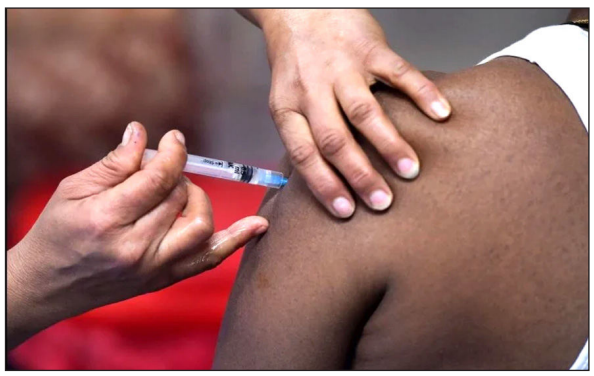

यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन तेज गति से किया जा रहा है... प्रदेश में अब तक ढाई करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों ही डोज ले ली है...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 74 लाख 85 हजार से अधिक कोविड वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। 9 करोड़ 21 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। यह टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी के 62 फीसदी से ज्यादा है। वहीं, 2 करोड़ 53 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। 17 फीसदी से अधिक लोग पूरी तरह टीकाकवर प्राप्त कर चुके हैं।

प्रदेश के 41 जनपदों में कोरोना संक्रमण का एक भी एक्टिव केस नहीं है जबकि 13 जिलों में एक-एक एक्टिव केस शेष हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1 लाख 71 हजार 729 सैम्पल की टेस्टिंग में 67 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया। कुल 14 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जबकि 16 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए।

वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 135 रह गई है, जबकि 16 लाख 86 हजार 976 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं।

स्विफ्ट डिजायर समेत 5 लाख का गुटखा जब्त

ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, दो आरोपी हिरासत में

बुलडाणा । धामनगाव बढ़े पुलिस थाना अंतर्गत लाल माती फाटे से पान्हेंरा ग्राम की ओर अवैध रूप से प्रतिबंधित गुटखा तस्करी होने की गुप्त सूचना मिलते ही सूचना के आधार पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी किशोर रमेश राजपूत ने एक स्विफ्ट डिजायर कार सहित 5 लाख, 45 हजार 200 रुपये का गुटखा जब्त किया।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 13 अक्तूबर को 12, 30 बजे के दरमियान मध्यप्रदेश की ओर से एक वाहन से अवैध रूप से गुटखे की तस्करी की जानकारी धामनगाव बढ़े को मिली थी। गुटखा तस्कर किसी कार का इस्तेमाल करने की पक्की खबर मिलने पर पुलिस ने लाल माती फाटे पर स्विफ्ट डिझायर कार को रोकने की कोशिश की मगर तस्कर कार लेकर भाग निकले। मौके पर मौजूद ट्राफिक पुलिस ने कार का पीछा कर के गुटखे से लदी कर ग्राम पान्हेंरा के समीप पकड़ी। कार से करीबन 660 विमल पॉकेट कीमत 130680, सात ही सुगंधित तंबाखू, किमत 14520 के सात स्विफ्ट डिझायर कर एम, एच, 28, अ ठ 2829 किमत 400000 लाख ऐसा कुल मिलाके 5 लाख 45 हजार 200 रुपय का माल जप्त किया जब्त किए गए। गुटखे कि कीमत बाजार मार्किट के हिसाब से 5 लाख 45 हजार 200 रुपये होने की जानकारी धामनगाव बढ़े पुलिस ने दी। पुलिस ने कुल साढ़े 5 लाख रुपये की साम्रगी जब्त की हैं

ट्राफिक पुलिस किशोर रमेश राजपुर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शेख सलीम शेख ईस्माइल,54, निवासी गोरख्शान वाडी चिखली ,सदीक शा मजीद शा, 24 निवासी चिखली के खिलाफ विविध धाराओं के तहत धामनगाव बढ़े पुलिस थाने में मामला दर्ज किया। आगे की जांच धामनगाव बढ़े के थानेदार चंद्रकांत ममताबादे के मार्गदर्शन में दुय्याम थानेदार अशीष गन्द्रे कर रहे हैं।

दरोगा ने चार साल तक युवती से किया दुष्कर्म, पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस में की शिकायत

मेरठ। मेरठ के ब्रह्मपुरी थानाक्षेत्र निवासी एक महिला ने गुरुवार को हस्तिनापुर में तैनात दरोगा अरुण कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एसएसपी ऑफिस पर हंगामा कर दिया। युवती का आरोप है कि दरोगा ने पिस्टल के बल पर उससे चार साल तक दुष्कर्म किया। वहीं इस मामले में एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने जांच बैठा दी है और एसपी देहात से रिपोर्ट मांगी है। जानकारी के अनुसार ब्रहम्पुरी थानाक्षेत्र निवासी एक युवती ने गुरुवार को एसएसपी ऑफिस पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। युवती का आरोप है कि दरोगा अरुण कुमार हस्तिनापुर थाने की भद्रकाली चौकी इंचार्ज उसके साथ चार साल से दुष्कर्म करता आ रहा है।

साठ हजार घर डेंगू की जद में

बरेली। तमाम कवायद के बावजूद डेंगू और मलेरिया के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मच्छरों के लार्वा की तलाश में पिछले सात दिनों में एक लाख घरों का सर्वे कराया जिसकी रिपोर्ट के अनुसार घरों के बाहर करीब एक फीसदी मच्छर पनपते मिले जबकि अंदर चार फीसदी लार्वा मिला। डेंगू फैलाने वाला मच्छर एडीज आसपास के 15 घरों तक पहुंच सकता है लिहाजा साफ है कि जिले के करीब साठ हजार घर डेंगू की जद में हैं।

अफसरों का दावा है कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जिले में मच्छरजनित रोगों की रोकथाम के लिए फॉगिंग, लावार्साइड स्प्रे, पायरेथ्रम स्प्रे कराया जा रहा है। बावजूद इसके डेंगू, मलेरिया के मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। ज्यादातर एक ही परिवार में दो से तीन लोग डेंगू या मलेरिया से ग्रसित मिल रहे हैं।

फ्रिज की ट्रे और कूलर में सबसे ज्यादा लार्वा

टीम के मुताबिक घरों के भीतर और खिड़कियों से सटाकर रखे गए कूलर और फ्रिज के पीछे की ओर लगी पानी की ट्रे (कंडेनसेशन प्लेट) की जांच की गई। इनमें भी मच्छरों का कुनबा तैयार होता पाया गया। इसकी जानकारी घर के लोगों को दी गई। उन्हें नियमित तौर पर इसकी सफाई करने को कहा गया।

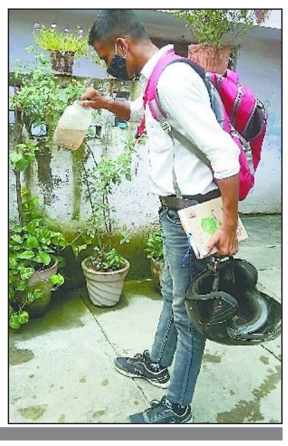

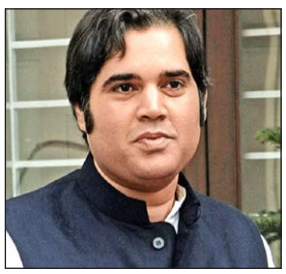

कृषि कानून: भाजपा सांसद वरुण गांधी ने फिर किया किसानों का समर्थन

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का एक बार फिर समर्थन किया है। गुरुवार को उन्होंने किसानों के समर्थन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने इशारों-इशारों में बता दिया है कि सरकार किसानों के आंदोलन का दमन कर रही है और ऐसे में वे अपने फर्ज को ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ खड़े हैं। गुरुवार को पोस्ट 41 सेकेंड के वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, एक बड़े दिल के नेता द्वारा कही गई बुद्धिमानी की बात। वीडियो तब का है जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे

वैज्ञानिकों ने किया दावा

कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को रोक सकता है ये नया एंटीवायरल कंपाउंड

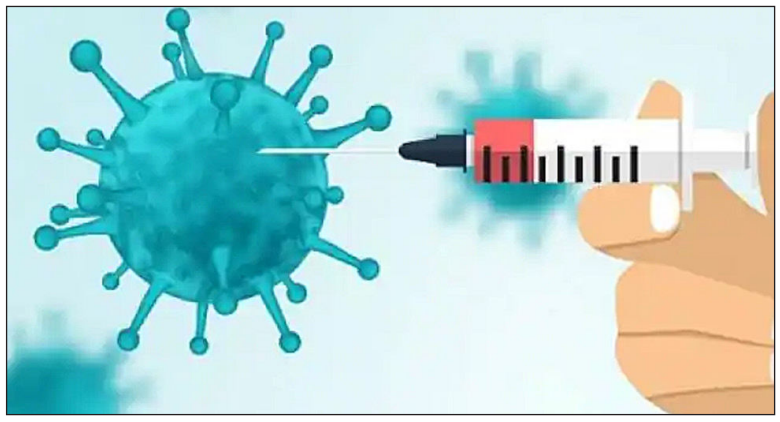

वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रासायनिक यौगिक को विकसित किया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह सार्स-सीओवी-2 वायरस से होने वाले संक्रमण को रोक सकता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अगर संक्रमण के दौरान जल्दी दिया जाए तो कोविड-19 की गंभीरता को कम कर सकता है।

अमेरिका में 'वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन' के शोधकर्ताओं के अनुसार, 'एमएम3122' नामक यौगिक कई वायरस की मानव कोशिकाओं पर हमले की एक प्रमुख विशेषता के साथ हस्तक्षेप कर उन्हें कमजोर करता है।

पत्रिका 'प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज' में बताया गया कि यौगिक, मुनष्य में पाए जाने वाले एक प्रमुख प्रोटीन 'ट्रांसमेम्ब्रेन सेरीन प्रोटीज 2' (टीएमपीआरएसएस2) को निशाना बनाता है, जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस भी मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने और उन्हें संक्रमित करने के लिए करता है।

अध्ययन के लेखक एवं वाशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेम्स डब्ल्यू जेनेटका ने कहा कि सार्स-सीओवी-2 रोधी कई टीके अब मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस वैश्विक महामारी की गंभीरता को कम करने के लिए प्रभावी 'एंटीवायरल' (वायरस रोधी) दवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस रासायनिक यौगिक को हम विकसित कर रहे हैं, वह वायरस को कोशिकाओं के भीतर जाने से रोकेगा।

जेनेटका ने कहा कि अध्ययन का लक्ष्य अणुओं को एक अवरोधक के रूप में विकसित करना है, जिसे मुंह से लिया जा सकता है और यह कोविड-19 रोधी दवा अवरोधकों का एक प्रभावी हिस्सा बन सकता है।

नेचुरल ग्लो के लिए करें कॉफी फेशियल

करवाचौथ के लिए महिलाओं ने अभी से तैयरी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में वह सबसे पहले अपनी स्किन और स्टाइलिंग पर ध्यान दे रही हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो स्किन पर ग्लो तो पाना चाहती है लेकिन बजट में रहते हुए साथ ही कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो फेस पर केमिकल वाले प्रॉडक्ट का इस्तेमाल करने से बचती हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो बजट में रहने के साथ ही नेचुरल हो तो आप घर में मौजूद कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कफी में एंटीएजिंग प्रॉपर्टी होती हैं, जो स्किन प्रॉब्लम से लड़ने में काफी मदद करती हैं। स्किन पर कॉफी का इस्तेमाल करने से चेहरे की फाइन लाइंस के साथ रेडनेस कम करने में मदद मिलती है। साथ ही अगर स्किन पर सनबर्न के स्पॉट हैं तो वह भी कम हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे करें निखरी त्वचा के लिए कॉफी फेशियल-

3 स्टेप्स में मिलेगी निखरी त्वचा

कॉफी स्क्रब

कॉफी स्क्रब बनाने के लिए आप सबसे पहले एक चम्मच कॉफी को आधा चम्मच चावल के आटे के साथ मिक्स करें और इसमें हल्की सा नींबू मिलाएं। इसे अच्छे से मिक्स करें और अपने चेहर पर लगाकर हल्के हाथ से मसाज करें। रगड़े नहीं आपको सिर्फ हल्के हाथ से मसाज करनी है। ऐसा करने से आपकी डेड स्किन हटेगी। साथ ही नींबू के कारण स्किन से गंदगी हटाने में भी मदद मिलेगी

कॉफी क्लिंजर

स्क्रब करने के बाद क्लिंजर करना जरूरी होता है क्योंकि स्क्रब के बाद स्किन के पोर्स खुल जाते हैं। कॉफी से क्लिंजर बनाने के लिए आप एक चम्मच कॉफी में 2 चम्मच दूध मिलाएं। इसे अपने चहरे पर लगा कर मसाज करें। मसाज करने से आपकी चेहरे की बोन्स और मसल्स को आराम मिलेगा और आपकी स्किन ग्लो करेगी।

कॉफी मास्क

कॉफी मास्क के लिए 1 चम्मच कॉफी में 1 चम्मच शहद मिलाएं और चेहरे पर अच्छे से लगाएं। अब इसे अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छे से लगा लें। फिर इसे 20 मिनट तक सूखने दें और बाद में अपने हाथों को गिला कर मसाज करते हुए हटाएं।

रात में लगती है भूख तो इन हेल्दी स्नैक्स को खाएं, नहीं बढ़ेगा वजन

क्या आप भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हैं जो रात का खाना खाने के कुछ देर बाद स्नैक्स तलाशते हैं? अक्सर लोगों को रात में भूख लगती है, ऐसे में वह लोग अनहेल्दी चीजों की तरफ चले जाते हैं और रात में कुछऐसी चीजें खाते हैं। रात में अनहेल्दी स्नैक्स खाने से सेहत पर गलत असर पड़ता है। अगर आप भी रात में बर्गर, नूडल्स या फिर ऐसी चीजों को खाते हैं तो आज ऐसा न करें क्योंकि रात में इस तरह के खाने को डाइजेस्ट करने में परेशानी होती है। आइए जानते हैं रात में भूख लगने पर क्या खाएं।

1) रागी चिप्स

रात में खाने के लिए रागी चिप्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें की ये चिप्स रोस्टेड या फिर बेक्ड हो। ये चिप्स हेल्दी हैं इसकी मतलब ये बिल्कुल नहीं की आप बहुत ज्यादा मात्रा में इन्हें खाएं।

2) रोस्टेड मखाना

अगर आपको रात में भूख लगती है तो आप एक मुट्ठी रोस्टेड मखाना खा सकते हैं। इन्हें तलना नहीं है इन्हें हल्का सा भून लें और फिर इसे टाइट कंटेनर में स्टोर कर के रख दें।

3) हर्बल टी

कई बार हम भूख और क्रेविंग में अंतर नहीं समझ पाते हैं। अक्सर रात में हमे क्रेविंग हो रही होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप रात में हर्बल टी या फिर ग्रीन टी पी सकते हैं।

4) मेवा

अधिक्तर हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 10 से 12 बादाम, मूंगफली, काजू और अखरोट बेस्ट स्नैक्स हैं। मेवा में फाइबर और गुड़ खा सकते हैं।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर